



भारत का चलापत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274]

नई दिल्ली, बंगलशाह, दिसम्बर 27, 1988/पी. 6, 1910

No. 274] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 1988/PUSA 6, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है। जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय
आयात व्यापार नियंत्रण
सार्वजनिक सूचना सं. 90 आई टी सी (पी एन)/88-91
नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1988

विषय.—उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यू. पी. एस ई. बी.) की अनपारा "बी" थर्मल पावर स्टेशन निर्माण परियोजना (2×5000 मेगावाट) पूर्ण करने के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) ऋण के अन्तर्गत उपस्कर/सेवाओं के आयात के लिए लाइसेंसिंग शर्तें

फाइल सं. आई पी सी/23/(47)/88-91---उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यू. पी. एस ई. बी.) की अनपारा "बी" थर्मल पावर स्टेशन निर्माण परियोजना (2×500 मेगावाट) पूर्ण करने के लिए ओ ई सी एफ ऋण के अन्तर्गत उपस्कर/सेवाओं को शामिल करने वाली शर्तें जो इस सार्व-

जनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है, सूचना के लिए
अधिसूचित की जाती है।

के. बी. इरनीराया, मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रण
वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 90 आई टी सी (पी एन)/88-91, दिनांक 27-12-1988 का
परिशिष्ट।

जापान की विदेशी प्रार्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा प्रदान किए गए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यू. पी. एस ई. बी.) की अनपारा "बी" थर्मल पावर स्टेशन की निर्माण परियोजना (2×500 मेगावाट) को पूरा करने के लिए ओ ई सी एफ ऋण के अन्तर्गत उपस्कर और सेवाओं के आयात के सम्बन्ध में लाइसेंस शर्तें।

खण्ड-1 सामान्य शर्तें

1. (1) जापान, सरकार ने ठन्की आधार पर यू. पी. एम. ई. बी. की अनपारा "बी" थर्मल पावर स्टेशन निर्माण

परियोजना (2×500 मेगावाट) को पूरा करने के लिए 100 विलियन येन के ओर ई सी एफ ऋण को बहुवर्षीय समय में प्रदान करते की स्वीकृति दी है। अब तक ओर ई सी एफ के साथ 38,395 विलियन येन की कुल ऋण धनराशि के लिए दो ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं) ओर ई सी एफ ऋण सं. आई डी-पी-20 जो कि 24.1 विलियन येन का है 26-12-1984 को हस्ताक्षरित किया गया और रों आई डी-पी-45 जो कि 14.295 विलियन येन का है, उसे 10-2-1988 को हस्ताक्षरित किया गया है। शेष ऋण राशि के लिए ऋण करार आगामी 2-3 वर्षों में परियोजना के लिए वार्षिक ओर ई सी एफ ऋण को भव्य नजर रखते हुए हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओर ई सी एफ) द्वारा प्रदान किया गया ऋण भारत और जापान सहित विकासशील देशों के लिए खुला है। तदनुसार, इस ऋण के अन्तर्गत अधिकारी की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्घृत सभी देशों से आयात की जा सकती हैं। ये देश ऋण के अन्तर्गत पावर स्टोर देश होंगे।

1. (2) फ्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मर्दों और उन्हीं मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महानिदेशालय, तकनीकी विकास/पूँजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो। इस फ्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस का मूल्य 110.0 विलियन येन (लागत-बीपा-भाषा) से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयात लाइसेंस का रूपए में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमाशुल्क) द्वारा अधिसूचित विनियम दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचालित दर और मूल्य नियंत्रक, आयात-निर्णय, द्वारा जारी की गई मार्वर्जनिक सूचना सं. 78 आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के रैस-2 के अनुसार आयात लाइसेंस में सुनकेतिक दर पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें यह भी उल्लेख होगा कि सीमाशुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (सों) में विनिर्दिष्ट मूल्य विनियम दर पर मूल्य को लाइसेंस मूल्य के नामें ढालेगा। लाइसेंस पर एक शीर्षक “जापानी येन ऋण” होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में “एस जे सी” कोड होगा। यह कोड यू. पी. एस ई बी को आयात लाइसेंस भेजते समय मुद्र्य नियंत्रक, आयात-नियर्ति के पद में भी दोहराया जाएगा, इस पद की एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

1. (3) इस ऋण के तहत आयात लाइसेंस केवल लागत-बीपा-भाषा के आधार पर जारी किए जा सकते हैं।

1. (4) यू. पी. एस ई बी/आयातक की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस इस फ्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं। लेकिन, कुल मूल्य

110.0 विलियन (लागत बीपा भाषा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैग (1) में बताया गया है।

1. (5) आयात लाइसेंस की वैद्यता में वृद्धि प्रायातक द्वारा आवेदन करने पर 12 महीनों की और प्रागे की अवधि तक दी जा सकती है। प्रागे और वृद्धि करने के लिए नथा प्रायात लाइसेंस जारी करने के लिए यदि कोई आवेदन हो तो उसे आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजा जाना चाहिए।

1. (6) फ्रेडिट के अधीन विस्तार किए जाने वाले आयात, आयात लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित आयात लाइसेंस से संलग्न माल और सेवाओं की सूची तक प्रसिद्धित है।

1. (7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। मार्तीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भुगतान मार्तीय अभिकर्ता को भारतीय रूपए में किया जाना चाहिए। लेकिन, पैसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और लाइसेंस पर द्वी प्रभारित किए जाएंगे।

1. (8) पक्के आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को जहाज पर्यंत निःशुल्क/लागत और भोड़ा मूल्य के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भोतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। यीपा प्रभार का भुगतान भारतीय रूपए में भारत में देय होगा। “पक्के आदेशों” का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्या आदेशों से हैं जो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्या संविदा होगा विवेणी संभरक के भारतीय अभिकर्ताओं के आदेश या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुस्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं हैं।

1. (9) चार महीनों की अवधि के भोतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेकों के पूर्ण धस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीने के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (जापान अनुभाग) को नहीं पहुंच जाने हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1 (8) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकते हैं, इन कारणों का उल्लेख करने वृत्त लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को संबंध प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश होने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक 4 महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों में

अधिक के लिए मानी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपेक्ष रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (जोपाल अनुमति), नर्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पावरता के आधार पर विचार करेंगे और अगला निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को देंगे। जिसको वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पव प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकूल व्यापारी और विभागीय प्राधिकारी आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों को पूर्ण करने के संबंध में साखपत्र स्थापित करते हैं तिए प्राधिकार पव और युल्य रूपया जमा करने आदि की स्वीकृति छत्यादि की सुविधाओं की अनुमति देंगे।

1. (10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से बार महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिए। माल के पोतलदान पर अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेके में नकद आधार पर अर्थात् पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक में भारतीय आयातक को किसी भी किसम की अण मुविधा उत्तरव्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित व्यवस्था होनी चाहिए—

“साखपत्र की प्राप्ति के बाद ————— महीने परन्तु अधिक से अधिक————— के अन्त तक पूर्ण किया जाना है।

पोतलदान के लिए आविरी तिथि निश्चित करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-12-1991 के बाद की न हो।

खण्ड-3 संभरण ठेके का सम्मीलीता करने समय ध्यान में रखो जाने वाली विशेष बातें—

2. (1) ठेका का जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत और भाड़ा भूल्य येन में (येन की भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होने चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो, तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रूपय में चुकाना चाहिए।

ठेके का युल्य भारतीय रूपय या किसी अन्य सुदूर में किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। क्य आदेश और संभरक द्वारा पुस्तिकरण आदेश ब्रेवल अंप्रेसी में होना चाहिए।

2. (2) परामर्शी सेवाओं को छोड़कर अनपारा “बो” अंप्ल यात्रा, परियोजना के लिए और ऐसी एक अण की जगह गे विन पोपित किए जाने वाले मध्य माल और सेवाओं

की अधिप्राप्ति और इसी एक अण के तहत अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार होगी।

(क) यू. पी. ऐस ई बी को भारत और सेवाओं की अधिप्राप्ति का वित्त पोपण पूर्व अहर्ता सहित औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा और दूसरी सविदा आधारित निविदा के माध्यम से अण की रकम से करना होगा।

(ख) यदि पूर्वभूती सहित औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से विश्व अधिप्राप्ति की प्रक्रिया का विकल्प अनन्तना चाहता है तो यू. पी. ऐस ई बी को इस पद्धति के लिए एक आवेदन पर जिस पर प्राधिकूल व्यक्ति के विविक्त दस्तखत हो प्रस्तुत करके पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

(ग) विजापन और/या पूर्वभूती अधिसूचित करने से पूर्व यू. पी. ऐस ई बी निधि को पूर्वभूती लेबों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगा। जब पूर्वभूती कमी का चयन कर निया जाएगा तो यू. पी. ऐस ई बी निधि को फर्मों की मूवी और चयन के सम्बन्ध में कारणों का उल्लेख करते हुए चयन प्रक्रिया रिपोर्ट, सभी सम्बद्ध प्रेसेबों को संलग्न करते हुए उसकी स्वीकृति देते हुए प्रस्तुत करेगा।

(घ) माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए बोलियां आमंत्रित करने से पूर्व यू. पी. ऐस ई बी सभी नोटिस और बोलीहारों के लिए अनुदेश, बोली प्राप्त प्रस्तावित ठेका, विशिलिकरण और द्राइंग और बोली में सम्बन्धित अन्य दस्तावेज निधि को स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करेगा।

(इ) सकूत बोलीकार को निर्गत का नोटिस जारी करने से पूर्व यू. पी. ऐस ई बी, बोलियों के विवेपग और ठेका देने के प्रस्ताव को निधि की स्वीकृत के लिए प्रस्तुत करेगा।

(ज) बोली सम्बन्धी दस्तावेजों में पात्र स्ट्रोत देशों को भी दर्शाया जाएगा।

2. (3) बदेशी संभरक को भ्राता, उनके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा ओर ईसो एफ येन क्रेडिट को (परियोजना सहायता) के अधीन खोल गए आरियांनीद मालवत के माध्यम से किया जाना चाहिए। योरा नोबे खण्ड-5 में दिया गया है।

2. (4) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्ट्रोत देशों के राष्ट्रिक होने या पात्र स्ट्रोत देशों में शामिल किए गए तथा पंजीकृत किए गए पात्र स्ट्रोत देशों के राष्ट्रिक होना यात्रित बैंक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास पात्र स्ट्रोत देशों में जड़ी वे अगला कारोगार करते हैं माल और सेवाओं के प्रस्तुतीकरण या प्रदान करने की उचित व्यवस्था हो।

2. (5) अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयात

जिन कस्तुओं में अपात्र स्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उनके लिए वित्तदान किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे उत्पाद में आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार, की प्रति इकाई कीमत के 50% से कम हो :—

आयातित लागत बीमा भाड़ा + आयात शुल्क

$\text{---} \times 100$

संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य (भारतीय संभरक के मामले में, कारखाने पर मूल्य अपनाया जाएगा)

2. (6) संविदा में घोषणा

प्रत्येक संविदा में संभरक द्वारा माल एवं संभरक की पात्रता और संभरक के हस्ताक्षर और तारीख से निम्नलिखित घोषणा जोड़ी जाएगी :—

“मैं अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि संभरित किया जाने वाला माल —————— (संबंधित पात्र स्रोत देश का नाम) में उत्पादित है।

“मैं अधोहस्ताक्षरी, आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी अपनकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 50% (पचास प्रतिशत) से कम है :—

आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयात शुल्क

$\text{---} \times 100$

संभरक का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (भारतीय संभरक के मामले में कारखाने पर मूल्य)

“मैं अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि —————— (कम्पनी का नाम) —————— को

————— (पात्र स्रोत देश का नाम) में समाविष्ट और पंजीकृत कर लिया गया है और यह (संबंधित पात्र स्रोत देशों का नाम) के शास्त्रिकों द्वारा नियंत्रित है।”

खण्ड-3 संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली भाँतें

3. (1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित विधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए।

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओं ई सी एफ) के बीच यू.पी.एस ई सी की अनपारा “बी” विद्युत यर्मल पावर परियोजना के लिए ओं ई सी एफ ऋण (परियोजना सहायता) से संबंधित ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओं ई सी एफ) के बीच हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अदरिवर्तनीय सालपत्र के माध्यम से किए जाएंगे।

(ग) संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओ ई सी एफ द्वारा येन ऋण के अधीन अधेश्वित हों।

(घ) उपर्युक्त 2(6) में उल्लिखित प्रधन में प्रमाण पत्र (तीन प्रतियों में)।

(ङ) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा में इस संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक, भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को शामिल माल की सुरुईगी के कार्यक्रम से अवगत कराएगा और पोतवान से कम से कम 6 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में जहां भारतीय आयातक इच्छुक हो, सूचना की इस प्रवधिकी की कम किया जा सकता है। जापानी संभरक को प्रत्येक पोतवान के पश्चात् आवश्यक व्यारे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसको एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड-4 ओं ई सी एफ द्वारा ठेके की स्वीकृति

4. (1) लाइसेंसदारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्वाचित अधिकारी के भोतर यू.एस ई बी और विदेशी संभरकों दोनों के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की घार प्रतियों जो विदेशी संभरकों द्वारा लिखित में पुष्ट आवेदन के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों संगत वैध आयात लाइसेंस को दो फोटो प्रतियों सहित और परिशिष्ट-2 के प्रधन में “प्राधिकार पत्र” जारी करने के लिए आवेदन की दो प्रतियों आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

4. (2) उपर्युक्त कियाविधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों को विश्व वस्तु के लिए ग्रन्तिवार्य आशोधनों के कारण होने वाले संशोधनों या उनको कीमतों पर भी लागू होंगी।

4. (3) वित मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान ग्रन्तिवार्य डेका प्रलेख की एक प्रति ओं ई सी एफ की स्वीकृति के लिए भेजेगा। साथ हो साथ प्रत्येक ठेकों की एक-एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को और सो.ए.ए.ए.ए.के कार्यालय को भेजेगा।

खण्ड-5 विदेशी संभरकों को भुगतान-साम्बन्ध प्रक्रिया विधि

5. (1) वित मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ओं ई सी एफ से ठेके की स्वीकृति की सूचना प्राप्त करने पर उसके सम्बन्ध में यू.पी.एस ई सी एफ ए.ए.ए.को सुचित किया जाएगा जिसके बाद यू.पी.एस ई बी को

सहायता देखा या लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे भागे सी ए ए एच ए कहा गया है), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यूको बैंक बिल्डिंग, संसद भार्ग से अनुबन्ध-2 में मंलग्न प्रदत्त में यह श्रवेदन करते हुए समर्क करना चाहिए कि वह सम्बन्धित विदेशी संभरक के नाम में संलग्न अनुबन्ध-4 के प्रधान में (आयातों के लिए) और अनुबन्ध-5 के प्रधान में (सूकाजों के लिए) अपरिवर्तनीय साधापत्र छोलने के लिए संलग्न अनुबन्ध-3 के प्रधान में बैंक आफ इंडिया और टोकियो भारता को सम्बोधित एक प्राधिकार पत्र जारी करें। प्राधिकार पत्र की प्रतियां ओ ई सी एफ, भारतीय दूतावास टोकियो, यू पी एस ई बी, भारत में आधारक के बैंक और आयात अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएंगी।

5. (2) प्राधिकार पत्र मिलने पर, बैंक आफ इंडिया, टोकियो अनुबन्ध-4 (आयातों के लिए) या अनुबन्ध-5 (सूकाजों के लिए) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साधापत्र करेगा और उसकी एक-एक प्रति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) भारतीय दूतावास टोकियो, भारत में आधारक के बैंक और सहायता देखा एवं परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा।

सी ए ए हैड ए से प्राधिकार पत्र के आधार पर साझ-पत्र छोलने के लिए उत्पत्ति विधाविधि प्राधिकार पत्र/साधापत्र में होने वाले ऐसे सभी संशोधनों पर स्वतः लागू होगी ओ संघिदा संशोधन या अन्यथा के लिए आवश्यक हों।

5. (3) माल का पोतसदात करने के बाद विदेशी संभरक प्रभाने बैंकरों के आधायम से साधापत्र में उत्पत्तिवाले भूगतान के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा यदि प्रत्येक सही बैंकरों के उन बैंकरों के माध्यम से यहां फरेगा और उसके बाद आयातों की लागत की घनराशि की प्रतिशुत विदेशी आर्थिक निधि से प्राप्त करेगा।

5. (4) साधापत्र छोलने, उसके अधीन सेन्ट्रेन करने सम्बन्धी प्रभार और यदि विदेशी संभरकों के बैंकरों के कोई अध्य प्रभार हों तो उन्हें आधारक/विदेशी संभरकों द्वारा चुकाया जाएगा। संविदा मूल्य के 1/10 प्रतिशत (0.1 प्रतिशत) के बराबर घनराशि की प्राप्ति होने पर ओ ई सी एफ द्वारा एक वर्षनवृद्धि पत्र जारी किया जाएगा यह घनराशि ओ ई सी एफ द्वारा ऋण/निधियों से स्वतः चुकाई जाएगी।

आधारक ओ ई सी एफ से या लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय से भूगतान की भूचता प्राप्त होने पर बचनवृद्धि बच्चों के इस पत्र के तुल्य स्पष्टा भारत सरकार के नेत्रों में जमा करना पड़ेगा। ओ ई सी एफ को भूगतान की निधि से ऊर स्पष्टा जमा करने की निधि उक (दोर्ता दिन

प्रतिशुत) का व्याज भी आधारक द्वारा खालू दर पर देय किया जाएगा।

प्रतिशुत प्रक्रिया के अवीन में इसी प्रकार 0.1 प्रतिशत के स्वर्वे आधारक द्वारा देय है। आधारकों द्वारा विदेशी संभरकों को आयातों की लागत के भुगतान वाली तिथि से जो ओ ई सी एफ द्वारा प्रतिशुत फी तारीख तक की अवधि के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय व्याज के खर्चे भारत में आधारक के सम्बन्धित बैंक द्वारा भारत सरकार के लेखे को प्रमाणित किए बिना सामान्य बैंकिंग चेनल के माध्यम से बैंक आफ इंडिया, टोकियो को दर्शित किए जाएंगे।

5. (5) प्रतिशुत क्रियाविधि

भारतीय संभरकों से माल और सेवाओं की खरीद के लिए ऋण की रकम की आदायी के लिए प्रक्रिया ऋण समझौते को प्रतिशुत क्रियाविधि के अनुसार होगी।

खण्ड 6—परामर्शदाताओं का नियोजन

परामर्शदाताओं का नियोजन ऋण समझौते से सम्बद्ध “विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से ऋण लेने वालों द्वारा परामर्शदाताओं के नियोजन में संबंधी मार्गनिर्देश” के अनुसार किया जाएगा ।

(1) परामर्शदाताओं का नियोजन करने वाली फर्मों को निम्नलिखित गते पूरी करनी होगी:—

- (क) अधिकांश अभिदत्त शेयर पात्र स्वोत देशों के राष्ट्रियों द्वारा धारित किए जाने चाहिए;
- (ख) अधिकांश पूर्ण कालिक निदेशक पात्र स्वोतों देशों के राष्ट्रिक होने चाहिए।

(ऐसी फर्में वात स्वोत देशों में निर्मित तथा पंजीकृत होनी चाहिए ।)

(2) निम्नलिखित के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग निधि का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त करना होगा:—

- (i) सेवा की गते
- (ii) परामर्शदाताओं की सभु सूची।
- (iii) आवंतन पत्र।
- (iv) संक्षिप्त मूल्यांकन शीट सहित मूल्यांकन रिपोर्ट।

(3) प्रत्येक संविदा के मात्र परामर्शदाता की पात्रता में संबंधित निम्नलिखित बोध्या, जिसपर परामर्शदाता द्वारा अपने हत्ताकार किए जाएंगे और तारीख द्वारी जाएंगी, मंलग्न होनी चाहिए :

“मैं, अधोस्ताकारों एकद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि (फर्म का नाम) पात्र स्वोत देशों का नाम में निर्मित तथा पंजीकृत है, और एक नात्र परामर्शदाती फर्म है जिसके प्रतिशुत (..... %) अभिवृत शेयर (संबंधित नात्र स्वोत देशों का नाम) के नापरिलों द्वारा धारित

हैं और इसके प्रतिशत (……%) पूर्ण कालिक निदेशक (संबंधित पात्र स्रोत देशों के नाम) के राष्ट्रिक हैं।"

(4) अगर जापान को छोड़कर किसी और पात्र स्रोत देश के परामर्शदाता को संविदा प्रदान की जाएगी तो संविदा के मूल्य का उल्लेख तथा भुगतान जापानी येन धा अनुसारी डालर में किया जाना चाहिए। जापानी परामर्शदाता को संविदा प्रदान करने की स्थिति में संविदा के मूल्य का उल्लेख तथा भुगतान जापानी येन में किया जाना चाहिए।

संविदा भारत सरकार/विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा अनुमोदन प्रदान करने पर ही को जाएगी।

(5) ऊपर कथित प्रलेखों को यूर्पी एस ई बी द्वारा निम्नलिखित का विवरण देते हुए आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से निधि को प्रमुख किया जाएगा :—

- (क) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा धारित अधिकार शेयरों का प्रतिशत।
- (ख) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक जो कि पूर्णकालिक निदेशक हैं, का प्रतिशत।

खण्ड 7-रुपया निष्केप करने के लिए उत्तरदायित्व

7(1) बैंक आफ दंगिया, टोकियो संगत प्राधिकार पत्र के परिणाम में यथा संकेतित आयातक के प्राधिकृत बैंकर को विनियेय जहाजी दस्तावेज भेजेगा और बैंकर इस बात का युनिश्वय करेगा कि जहाजी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी में रुपया निष्केप कर दिया गया है। प्रथम '30 दिनों के लिए समय-समय पर ज्ञालू वर्तमान 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से गिनी गई येन भुगतान के समनुल्य रूपये के लिए ब्याज प्रभार और उसमें अधिक की अवधि के लिए वास्तविक रुपया निष्केप करने की तारीख से विदेशी संभरक को बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तारीख तक 18 प्रतिशत की दर में प्रभार भी मूल धनराश के साथ सार्वजनिक सूचना सं. 31-आईटी सी (पीएन)/83, दिनांक 10-8-83 के अनुसार जमा करने पड़े।

इस बात को नोट कर लिया जाना चाहिए कि इन दोनों दिनों अर्थात् जिस तारीख को भुगतान किया जाता है और जिस तारीख को सार्वजनिक सूचना सं. 103-आईटी सी (पीएन)/78, दिनांक 12-10-76 और सार्वजनिक सूचना सं. 31-आईटी सी (पीएन)/83, दिनांक 10-8-83 द्वारा धनासंगोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74-आईटी सी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 के अनुसार ब्याज लिया जाएगा।

आयातक को संभरक को किए गए मूलतान की धनराश और टारीफ़ों का निरूपण परन्तु के लिए बाला से व्यवस्था करनी चाहिए। बैंक आफ इंडिया, टोकियो ने

प्रायतक के बैंकर द्वारा जहाजी दस्तावेजों आदि की रेटी से प्राप्ति को क्षमा निष्केप पर देर ब्याज की आंशिक धनराश पूरी बनराश की घटक के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समनुल्य रूपये की गणना करने के लिए अपनाइ जाने वाली विनियम की दर भुगतान की तारीख को लागू विनियम की वह मिथित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं. 109-आईटी सी (पीएन)/74, दिनांक 3-8-74 और सं. 8-आईटी सी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित वीर्य की गई हो जो मूल नियंत्रक, आयात-नियात की सार्वजनिक सूचनाओं के भाष्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिषदों के भाष्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो।

इस मंबंध में और ब्याज की दर के मंबंध में भी जब भी कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। यह मुनिश्चित करने के लिए मंबंधित भारतीय बैंक की जिम्मेदारी होगी कि देव धनराश आयातकों को आयात दस्तावेज सौधिते से पहले सरकारी ब्राति में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। आयातकों को भी यह मुनिश्चित कर लेना चाहिए कि देव धनराश अनुसार अनुदानाओं से दस्तावेजों की सुपुर्दी लेने से पहले सरकारी ब्राति में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। यह मुनिश्चित करने के लिए आयातकों की जिम्मेदारी होगी कि देव धनराश सरकारी ब्राति में ठीक प्रकार से तुरन्त जमा कर दी है भले ही ये विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत शीमाशुल्क प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दी भूल दस्तावेजों के बिना प्राप्त करते हैं। यदि आयातकों सरकार को देव धनराश को माल की सुपुर्दी से पहले जमा नहीं कर पाता तो आगे के लिए उसे प्राधिकार पत्र देना बंद कर दिया जाए और गमले की रिपोर्ट मूल्य नियंत्रक, आयात नियात को दी जाए ताकि ऐसे आयातकों को आगे और आयात लाइसेंस जारी न किए जाएं। जिस लेबा शीर्ष में उत्तरुक रूपया निष्केप किया जाएगा वह "के डिगोजिट्स एण्ड एडवांसेज 843-सिविल डिगोजिट्स एडिगोजिट्स फार परेजिन अट्स्ट्रा एक्साइट-परवेज अण्डर केडिट्स/ओ ई सी एफ लोन एग्रीमेंट्स" (लोन फोम दि गवर्न-मेंट आफ जापान फार दि अनुसारा "वो" धर्मल पावर स्टेशन कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है)।

7(2) ऊपर उल्लिखित धनराश या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जातान के ऊपर दाइनी और कोने में कोड सं. 5130000009 का संकेत देते हुए सरकार के ब्राति में सार्वजनिक सूचना सं. 184-आईटी सी (पीएन)/68, दिनांक 30-8-1968, सं. 233-आईटी सी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-1968, सं. 132-आईटी सी (पीएन)/(71, दिनांक 5-10-71 सं. 74-आईटी सी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आईटी सी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 में उल्लिखित धनराश या करनी चाहिए।

7(3) भारत गरकार, वित्त मंत्रालय, आधिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर भारत में आयातक का संबंधित बैंक भी उपर निर्धारित तरीके से यह अतिरिक्त धनराशि मेवा खत्तों के निमित्त भेजेगा जो विन मंत्रालय (आधिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालयों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों द्वारा इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71 के पैरा-3 में निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेण्य और प्राधिकारी" (यदि कोई हो) के पूर्ण व्यारे में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट की गई है। खजाना चालान में निम्नलिखित और निरपवाद रूप से प्रस्तुत करते चाहिए।—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक

(ख) ये न मुझ की यह धनराशि किसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के सार्थ निधेय किए जाने हैं।

(ग) विदेशी संभरक की भुगतान करने की सिधि।

उसके पासवात् मीएए एण्ड ए द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजिंक तथा जहाजी दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान में संख्या जम्भा करने का माध्य देते हुए उसे पंजीकृत डाक द्वारा मीएए एण्ड ए को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी :— भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बैंक आफ इंडिया ट्रोकियो से अदायगी की सूचना और विनियम जहाजी दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर संख्या निक्षेप निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद मीएए एण्ड ए वित्त मंत्रालय (आधिक कार्य विभाग), नहीं विल्पी को इस तथ्य से सूचित कर दिया गया है।

7(4) भारत में संबंध भारतीय बैंकों लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति परहपया नियोजितों की धनराशि का पृष्ठोंकन करना चाहिए और अपेक्षित "एम" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक, बल्कि को भेजना चाहिए।

माण्ड 8-विविध व्यवस्थाएँ

8(1) आयात लाइसेंस का उपयोग करने की टिप्पोर्ट मालपद खोलने के बाद आयातक को पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में एक मालिक रिपोर्ट सहायता ज्ञा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आधिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यूको बैंक विनियम, संसद मार्ग, नहीं दिल्ली को भेजनी चाहिए।

8(2) संभरकों को विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना।

लाइसेंसधारी के आयात लाइसेंस में दिए गए ऐसे किसी विशेष उपबन्ध से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो सौदा करने में संभरक पर प्रभाव आलता हो।

8(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इंडिया, ट्रोकियो द्वारा किए गए भुगतान से वहने संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों के बारे में आयातक को अनुबन्ध-2 में "भुगतान की शर्तों" के अंतर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना चाहिए। मंविदा की शर्तों में विवादों को निपटाने में सम्बन्धित प्रावधान शामिल होने चाहिए।

8(4) भाशी अनुदेश

आयात लाइसेंस से उत्पन्न या उसमें सम्बन्धित किसी एक भागने या सभी मामलों के सम्बन्ध में और जापान की विदेशी आधिक सहयोग नियम (ओईसीएफ) के माध्य किए और इसी एक अृण करार (परियोजना सहायता) के तहत सभी दायित्वों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय पर जारी किए गए निर्देशों, अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

8(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त घटनों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-नियंत्रित (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उनित्र कार्रवाई की जाएगी।

8(6) अनुबन्धों की सूची

1. अनुबन्ध-1 पात्र स्वोत देशों की सूची
2. अनुबन्ध-2 प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध।
3. अनुबन्ध-3 प्राधिकार पत्र का प्रपत्र
4. अनुबन्ध-4 मालपत्र का प्रपत्र (आयातों के लिए लागू)
5. अनुबन्ध-5 मालपत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)।

उपांक्ति — 1

पात्र स्वोत देशों की सूची

क. विकासशील देश तथा उसके भेत्र

(क-1) पैदलियम नियंत्रित करने वाले देशों के संगठन से मिल विकासशील देश

1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा

विश्व

मोरक्को
तुनीशिया
2. अफ़्रीका, देलिंग सहारा
अंगोला
बेनिन
बोस्वाना
बर्बन्डी
केमरोन
केप वडे द्वीप
भव्य अफ़्रीका भवतंत्र
चाड
कोमारो द्वीप
कांगो, दाहोरे का गणतंत्र
हाफ्फेट्रोएरिप्स गिनी (I)
इथोपिया
जाम्बिया
धाना
गिनी
आइवरी कोस्ट
केनिया
लेसोथो
लाइबेरिया
भालागासी गणतंत्र
भालाबी
भाली
मारीशस, मारिटोरीनिया
भौजाम्बिक
नाईगर
पुर्तगाली गुयाना
रियूनियन
रोडेशिया
रवाण्डा
सेंट हेलिसा और द्वीप (2)
साओ टोमो और प्रिंसिपल
सेनेगल
सीचलीज
सीयरे सिङ्गान
सोमालिया

(1) पहले सेन गिनी का प्रदेश फरनाडो पो द्वीप सहित
(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित— एस्केनियन द्विराट्टी
इन एक्सेसिबस्स नाइट्रोनेस-गफ

(3) मुख्य द्वीप समूह अरब्बा बोलाइरे ब्युराकाओ, साहा, सेंट

सूडान
स्विटज़रलैण्ड
टेरो अपगर्स और इलास
टोमो
यूगाण्डा
तंजानिया गणतंत्रीय संघ
अपर बोस्टा
आइरे गणतंत्र
जाम्बिया
3. अमेरीका, उत्तरी और केन्द्रीय
बहूप्यास
बरमूडा
बार्बीडोस
बेसोज
कोस्टा रिका
क्यूबा
डोमिनिकन गणतंत्र
एल सेल्वाडोर
गुडासोप
ग्वाटेमाला
हेटी
होण्डूरस
जर्मीना
मार्टीनिक
भैंडिसको
नोदरलैण्ड एस्टीसीज
निकारागुआ
पनामा
सेंट पियरी और मिकेनोन
ट्रिनिडाड और टोबागो
3. अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय
वे स्ट्रैडीज (शाखा) एन. अर्थात
(क) सह-सम्बन्ध राज्य (1)
(ख) आश्रित (2)
4. दक्षिणी अमेरिका
अर्जेन्टीना

(1) मुख्य द्वीप एन्टिक डोमिनिका प्रेनडा, सेन्ट किट्स (सेन्ट किट्सोप्जे) नेविस-बंगुइसा सेंट लुसिया और सेन्ट विसेट

(2) भेन आईलैण्ड, थोलेसरल, सेमान तुर्क और काइकोल और विटिंग अंडिन द्वीप समूह।

बोलिंगिया	आइसैण्ड
ब्राजील	तिमोर
चिली	वियतनाम गणतंत्र
कोलम्बिया	वियतनाम जनवादी गणतंत्र
पश्चिम कोलंड द्वीप समूह	
प्रगंस गिनी	8. आौसिनिया
गुयाना	कुक द्वीप समूह
पराग्वे	फिजी
पोर्तुग	गिल्वेट और हलाइस द्वीप
सूर्खिनाम	फांसिस पौलिनेशिया (5)
यूरूप्पे	नारू
5. मध्य पूर्वी एशिया	न्यू केलेञ्चोनिया
बहरीन	न्यू हैंड्रिसिस (ब्र. और क्र.)
ईजराइल	निमू
जोड़न	पैसोफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
लेबनान	पापुआ न्यू गिनी
ओमान	सोलोमन द्वीप समूह (क्रा.)
सिरियाई अरब गणतंत्र	टोगा
यूनाइटेड अरब अमीरात (3)	बालिस और फुल्ना
यमन अरब गणतंत्र	पश्चिमी सामोआ
यमन जनवादी गणराज्य	9. यूरोप
6. दक्षिणी एशिया	साईप्रेस
अफगानिस्तान	जिब्राल्टर
बंगलादेश	ग्रीस
भूटान	माल्टा
वर्मां	स्पेन
भारत	तुर्की
क्यूराकाओ साहा सेन्ट	यूगोस्लाविया
मालद्वीप	(5) सोसायटी आई लैण्ड्स समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्रल द्वीप समूह, टुआमोद - बोम्बियर मुप और मारकोस द्वीप समूह।
नेपाल	6. पैसिफिक द्वीप का ट्रस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप, मार्शल द्वीप समूह और मरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)
पाकिस्तान	(क-2) ओ. पी. ई. सी. के सदस्य या सहयोगी देश
श्रीलंका	अल्जीरिया
7. सूदूर पूर्वी एशिया	बोलिया
बर्लनी	लीबियाई अरब गणतंत्र
हांग-कांग	गेबोन
खंगेर गणतंत्र	नाइजीरिया
कोरिया गणतंत्र	इक्वेडोर
लाओस	वेन्जुएला
माकाओ	ईरान
मलेशिया	ईराक
फिलिपाइन	कुवैत
सिंगापुर	कतार
ताइवान	सऊदी अरब
(3) अजमत दुर्बई फुजीराह रास अल्खेमाह शारजाह और अम्म अल कब्यायन।	आबू-धाबी
(4) अदन और विभिन्न सल्तनत और अमीरात सहित।	हॉन्डॉरेस शाया

प्राधिकार पक्ष आरी करने के लिए आवेदन पत्र

संख्या

विमोचन

लेखा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियमक,
वित्त मंत्रालय, आधिक कार्य विभाग,
यूनाइटेड कम्पनियस बैंक विलिङ्ग, प्रब्लम बैंगिल,
पालिबांडे ट्रीट, नवी दिल्ली-110001

विषय : येन क्रेडिट सं. आई.डी.पी.

(1988 के लिए परियोजना सहायता) के अंतर्गत
का आयात

महोदय,

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट सं. आई.डी.पी. (परियोजना सहायता) के प्रश्नोत्तर से का आयात के सम्बन्ध में (बैंक का नाम) जो कि वही होना चाहिए, जो नीचे (३) में सम्बद्ध विदेशी संभरक के नाम में साथ पक्ष खोलने के लिए दिया गया है कि पक्ष में प्राधिकार पक्ष आरी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित घोरे प्रस्तुत करते हैं:—

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता।
- (ख) आयात लाईसेंस की हंड्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक बैंक है।
- (ग) अधिप्राप्ति के तरीके का वह सीधे क्रम पर आधारित है या औपचारिक खुनी अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में कारणों सहित यह निविट करना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय अनुप्रृक्त तकनीकी प्रस्ताव के प्रावाह पर किया गया है।
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण।
- (ङ) माल का उदयन देश।
- (च) यदि कोई हो, तो पात्र से इतर लोत देशों से आशातित संघटकों का प्रतिगत।
- (छ) संविदा का कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क/लागत और भाड़ा मूल्य (येन में)।
- (ज) यदि कोई हो, तो भारतीय एजेंट के कमीशन की घनराशि (येन में)।
- (झ) वास्तविक जहाज पर्यन्त निःशुल्क/लागत और भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पक्ष माना जाए है।
- (ञ) विदेशों के संभरकों के साथ की नई संविदा की संख्या एवं दिनांक।
- (ट) विदेशी संभरक का नाम भार पता।
- (ठ) वे भुगतान शर्तें और संभावित स्थिरियां जिनको संविदा के अंतर्गत भुगतान देंगे होंगी।
- (ड) सुपुर्फी को पूर्ण करने की प्रत्यागत लिपि।
- (ढ) बैंक भारत इंडिया, टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत किया जाने वाले वस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निष्ठान दिखाते हुए)।
- (ण) पोडलदान अनुवेश (वाहनान्तरण/पार्ट-शिपमेंट) की अनुमति दी जाए है या नहीं, निर्दिष्ट कीजिए।
- (त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।
- (थ) क्या उसी लाईसेंस के अंतर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई है और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दिया गया है, यदि हाँ तो ऐसी प्रत्येक संविदा की संख्या, दिनांक और मूल्य का वह संदर्भ जिसके अंतर्गत ओ.ई.सी.एफ. को इसे प्रधिसूचित किया गया है।
- (द) क्या साथान के संचालन और रख-रखाव के लिए बैंक भारत इंडिया, टोकियो को वेय बैंक जैसे आयातक बैंक द्वारा या संभरकों द्वारा बहुन किए जाने हैं।
- (घ) आयातक द्वारा बचनबचता :—

“हम एतवदाया भरकार द्वारा निर्धारित तरीके से और दर से विदेशी संभरक को किए गए भुगतान के समतुल्य रूपए को पूरा और सही जमा करने का बहन देते हैं। प्रत्येक निषेप माल (आयातित सामग्री) की सुपुर्फी लेने से पूर्व स्तकात ही जमा करा दिया जाएगा। विदेशी संभरकों के सम्बन्धित वीजक हमारे द्वारा अनुमोदित होते ही और उनको प्रदायणी करते ही विदेशी रायिट्स की सेवाओं के मामले में निषेप कर दिया जायेंगे और संभरकों को भुगतान कर दिया जाएगा।”

उपायमध्य-३

(प्राथिकार पत्र का व्रपत्र)

(सं.)

(भारत सरकार)

वित्त मंत्रालय

प्राथिक कार्य विभाग

सेवा में

चैक अफ इंडिया

द्वितीयो शासा।

टोकियो (जापान)

विषय : मेन क्रेडिट (परियोजना सहायता) छूट करार सं

आई.डी.पी. —————— के अधीन अ.यास ।

नाब्रह्म औरने के लिए प्राविकार फ़द जारी करना ।

प्रिय महोदय,

आपको बैंक के साथ दिनांक 25-3-80 को किए पार समझते की जर्ती पर के अनुसार आपसे एउटारा यथा तंत्रज्ञ डीरे के अनुसार सर्वश्री _____ के नाम में _____ ऐन घनराति के लिए अविवरणीय दावात्र खोलते के लिए प्राप्तिहत किया जाता है।

2. प्राप्तके बैंक द्वारा जोले गए प्रस्तेक सार्व पक्ष की प्रति आवासक के बैंक, ओ.ई.सी.एफ. अमर्तदेव द्वारावास, टोकियो और हमें पुष्टाधित की जाए।

3. साक्षपत्र को पर्ती के अनुसार प्राप्तमें संवरहों के भूगतान आपको विधि में दिया जाएगा। आप लो०६०स्थ० एक को आवश्यक दस्तावेज़ सेवा कर किए गए भगतान की प्रतिपत्ति का दावा तकाल करें।

4. विदेशी संभरकों को प्रदायगी करते समय प्राप्तके हारा —————— (प्रायोतक के बैह के नाम व पता) मूल पोतमधान वहतावेष (विनियमन), प्रतिक्रिय पूर्ण इतावेजों के सेट के साथ तब संभरक को मई प्रदायगी को नार्म डालने की सूचना, तरकात प्रदायगी, मदि कोई की पर्द हो, तो उसकी प्रति भेजे ।

5. संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से ओ.ई.सो. एक द्वारा प्राप्त उत्तमी प्रतिरूपी की तिथि तक के बीच के समय के लिए आपको चुकाए जाने वोध्य भारत प्रभार भारत सरकार के लेखे पर प्रभाव इसे बिना सामान्य बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से भारत में संबंधित प्राप्तक के बैंक के साथ आपके द्वारा निर्णीत किए जावेंगे। बैंकों के अन्य खर्च विषम से साकारत खोलने, रख-जाकार करने और साकारतों के संवालन करने और सीदा संबंधी दस्तावेजों के संवालन से संबंधित और यदि कोई हो, तो विवेती संस्करण के बैंकरों के खर्च और विवेती ग्रंथारक/प्राप्तक को ही देने पड़ेंगे और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरक/प्राप्तक से प्राप्त किया जाए। इस प्रकार के भुगतानों को प्रदिव्युति कारबादा ओ.ई.सो.एफ. से नहीं किया जाएगा।

6. जैसे ही भाषके द्वारा कोई भुगतान किया जाए और उसको प्रतिपूर्ति प्राप्त को कर दी जाए तो उसकी सूचना निर्धारित पत्र में इस मंदाब्यक्ति को ऐसे दी जाती आहिए।

७. यह प्राधिकार पत्र विदेशी संस्करणों के नाम में साख पत्र खोलने के लिए है। साखपत्र में थार में किए जाने वाले संकेतन या प्राधिकार पत्र में मद्दे अविष्य में साखपत्र इन मंत्रालय से विदेश प्राधिकार प्राप्त किए जिना चाही नहीं होगे।

8. यह प्राप्तिकार पूर्ण तक वैध रहेगा ।

९. बुधपा इस करार से संबंधित सभी प्रश्नाचार और भूगतान का उल्लेख करने वाले गूचना पत्र में इस मनुदेश पत्र के शीर्ष पर दी गई संक्षया का उल्लेख करें।

भारतीय

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. भायातके _____ को उसके पत्र सं. _____ दिनांक के _____ के संबंध में ।

उनसे अनुरोध है कि वे बैंकरों से विनियम दस्तावेजों की डिलीवरी लेने से पूर्व निर्धारित वर पर और तरों से आपने बैंकरों के माध्यम से रुपया निक्षेप आदि जमा कराने का प्रवधन करें। यदि यिसेष परिस्थितियां के कारण माल की डिलीवरी सीधे ही सीमाशुल्क और पतन प्राधिकारियां से मूल पोतलदान दस्तावेज भेजे जिन स्थिति कर सी गई हो तो डिलीवरी लेने से पूर्व ही निक्षेप किए जाने चाहिए। विवेणी राज्यों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही सम्बद्ध बीजक भुगतान के लिए अनुमोदित हो जाए, निक्षेप कर दिए जाएं। निक्षेप जल्दी ही और टीक में न करने पर लाइसेंस की गती में यथाउलिकित प्रावधनक कार्यवाही की जा सकती है।

2(1) भायातके बैंक _____ यह भायात लाइसेंस सं. _____ दिनांक _____ के संबंध में है। यह प्राधिकार पत्र येन फ्रेडिट के अंतर्गत भायातों को शासित करने वाली संघीयत लाइसेंस गती के तहत जारी किया गया है। लाइसेंस गती और संघीयत सार्वजनिक सूचनाओं आदेशों को बेचें और आयात/विवेशी भुगतान करते समय उचित कार्रवाई करें।

2(2) उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक भायाक इंडिया, टोकियो जाव से दस्तावेज प्राप्त करते पर विदेशी संभरक को येन भुगतान के बराबर रुपये जमा करने की अवधारणा करें। संभरकों को भुकाई नई घनराशि के बराबर रुपये को गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8-भाईटी सी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-1976 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रश्नित परिवर्तन की निर्दिष्ट दर पर की जाएगी। प्रथम 30 दिनों के लिए 12% वार्षिक दर से और इससे अधिक अवधि के लिए 18% वार्षिक दर से आज जो कि संभरक को भुगतान भी तारीख /बैंक भायाक इंडिया को प्रतिपूति भी जारीब और जिस तारीख को सम्मुल्य रुपया भारत सरकार के लेखों में जमा किया जाए उन्होंने अवधियों के बीच की अवधि के प्रवधि के लिए संगणित करके उसे भी सार्वजनिक सूचना सं. 31-भाईटी सी(पीएन)/83, दिनांक 10-8-1983 के अनुसार भारत सरकार के लेख में जमा कराना है। आज दोनों दिनों के लिए देव है अवधि, वह तारीख जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और यह भी तारीख जिसको भारत सरकार के लेख में रुपया जमा कराया जाता है (जब भी इस दर में परिवर्तन किया जाए उत्ते सुचित कर दिया जाएगा)। यह सुनिश्चित करलेना चाहिए कि भायातक की सीमाशुल्क निकासी के लिए भायात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह घनराशि जमा की जानी है।

वे घनराशियां या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तोस हजारी में जागतान के दाहिनी और कोड सं. 5130000009 दराते हुए जमा करनी चाहिए। इस संबंध में उनका घ्यान सार्वजनिक सूचना संख्या 184-भाईटी सी (पीएन) 68, दिनांक 30-8-1968, भाईटी सी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-1968, 132-भाईटी सी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-1971, सं. 74-भाईटी सी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-1974, संख्या 103-भाईटी सी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-1976 में दिए गए भायातों को ओर दिलाया जाता है। यह लेख शीर्ष जिसमें ८० जमा कराना है, “के डिजिटल एंड एड्वाइसिंग-८४३-सिलिं डिजिटस-डिजिटस कार परवेजिज एडवीस्ट्री अवरोध अव्वर परवेजन फ्रेडिट/लोन एप्रोमेट्स” सोन कोष वा गवर्नरेंट भायाक जापान — विलियन येन फ्रेडिट (परियोजना सहायता) सं. भाईटी पी.....फार 198--8 है।

जिन भायातों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक भायाक इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक भायाक इंडिया, तोस हजारी विल्ली में सार्वजनिक सूचना सं. 132-भाईटी सी (पीएन)/71, दिनांक 3-10-1971 के अनुसार मकद जमा किया जाए उन मामलों में जागतान की मूल रुप में एक प्रतिलिपि उनके द्वारा मिन्निश्चित पते पर भेजनी चाहिए, जिसके साथ बैंक भायाक इंडिया, टोकियो जाका से प्राप्त सूचना टिप्पणियों का पूर्ण विवरण देते हुए एक अप्रेवन पत्र होना चाहिए।

सहायता लेखा तथा सेखा परीक्षा नियमक,
वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग),
पूर्वी मंत्रिल, यूनाइटेड कम्पनियल बैंक ट्रिलिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

जिन भायातों में तुल्य रुपया जार रक्तिक सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दरानी हुए ही द्वारा प्रेषित करना है उसकी सुचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में जमा किए गए तुल्य रुपये का पूरा अंश इस विभाग को भेजना चाहिए।

संभरक को भुगतान करने की तिथि और ओ.ई.सी.एफ. द्वारा बैंक भायाक इंडिया, टोकियो को उसकी अदायगी की तिथि के बीच की अवधि के लिए बैंक भायाक इंडिया, टोकियो को देव आज प्रभार बैंक सूखों के माध्यम से भारत सरकार के लेखे पर प्रभार जाने विना बैंक भायाक टोकियो के साथ आपके द्वारा सीधे निषित किए जायेंगे।

3. नियेशक, शृण विभाग-2 विदेशी आर्थिक लहरोग निधि टाकेवासी गोदो ब्रिलिंग, 4-1 ओ इटेमासी-1 कोमें, वियोजाक, नोकियां 100, जापान ।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो ।

5. अवर सचिव, जापान अमूभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ।

(लेखा अधिकारी)

प्रपत्र भ्रो.ई.सी.एफ.एल. सी.-1

अपरिवर्तनीय साक्षपत्र

(माल के लिए लागू)

दिनांक

सेवा में,

वह साक्षपत्र (झणी) और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के थोड़े हुए ऋण करार संबंध
के अनुसरण में जारी किया गया है।

दिनांक

महोदय,

हम आपको सुनित करते हैं कि हमारे नाम में भेजे गए आपके पूरे बीजक मूल्य के सिए आप के साहृदारों द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने आपके पक्ष में अपरिवर्तनीय साक्षपत्र सं— खोल दिया है जो— (प्रथम् येन) की कुल धनराशि से अधिक नहीं जिसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने आहिए :—

हस्ताक्षरित पूर्ण वाणिज्यिक बीजक, पोर्ट परिवहन सदान विल निसमें दिए गए आवेदों का पूरा सैट हो, अलैंक प्रूफ़ाक्तित एवं चिन्हित “फ्रैंट एवं नोटिफिकेशन” अंकित किए हुए प्रथम दस्तावेज।

जिनमें पोतलवान (माल के सदान का संक्षिप्त) को प्रमाणित करते हुए संविदा सं— (यदि कोई हो) के संबंध में—
से— तक आंशिक पोतलवान स्वीकृत है। बाहुनांतरण स्वीकृत है ड्राफ्ट— के बाद की तिथि का महीने प्रस्तुत किए जाने आहिए। इस ऋण के अंतर्गत सभी ड्राफ्ट तथा दस्तावेज पर ‘‘अपरिवर्तनीय साक्ष पक्ष सं— बिना सेन देन के’’ लिए प्रबंधन— के अंतर्गत आहरण किया गया और आयात संबंध में— (संभार) यदि कोई हो, अंकित होना आहिए।

यह क्रेडिट हस्तांतरणीय नहीं है।

हम एवं द्वारा बचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अंतर्गत और इस को जल्दी के अनुपालन में हमारे नाम में भेजे गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करते पर और आवेदितों को दस्तावेजों की सुरुदी पर विधिवत् स्वीकार किए जायें।

जब तक अस्थाय सम से उत्तेजना किया जाए यह क्रेडिट “मूलिकार्म कस्टम एण्ड प्रैक्टिस फार आकुमेंट्स ड्रेडिशन (1974 रिवीजन) इंटरसेशनल ऐम्बर आफ कामर्स, पर्टिकुलेशन सं. 290” के प्रधीन है।

1. उपर्युक्त ऋण करार के अंतर्गत विवेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा जारी किए गए बचन वक्त वी अवस्थाओं के अनुसार विवेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम बचन देते हैं कि हम सेनदेन करते वाले वैक द्वारा जारी किए गए प्रतुदेशों के अनुसार ड्राफ्टों की धनराशि को छोटा दें।

2. सेन-देन करते वाले वैक को यह बताते हुए हमें ड्राफ्ट और दस्तावेजों का एक पूर्ण सैट और उसके साथ एक प्रमाणपत्र प्रबंध भेजना आहिए कि वो एवं दस्तावेज सीधे ही हृषाई द्वाक द्वारा— को भेज दिए गए हैं।

3. इस क्रेडिट के अंतर्गत सभी वैक के बावें आयातक/संभारक के बाबें में देय हैं।

अबदीय,

विविधिक में

द्वारा—

प्राधिकृत हस्ताक्षर—

भुगतान शर्ते

मह भुगतान शर्ते हमारे साक्षपत्र सं— का एक प्रभित्र प्रेग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि— येन

कुल संविदा मूल्य का— प्रतिशत है।

प्रयोगित दस्तावेज :

अंतिम भुगतान तिथि :

2. मध्यस्थ भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि— येन

कुल संविदा मूल्य का— प्रतिशत है।

प्रयोगित दस्तावेज :

प्रस्तुत करने वी अंतिम तिथि :

3. पोर्ट परिवहन दस्तावेजों के मध्ये भुगतान

धनराशि— येन

कुल संविदा मूल्य का— प्रतिशत है।

टिप्पणी :—यह संस्करण पोर्ट परिवहन दस्तावेजों के मध्ये पूर्ण भुगतान के मामलों में प्रयोगित नहीं है।

उपाधिका—5

प्रपत्र ओ ही सी एक एल-सी-2
 (अपरिवर्तनीय साख्यक्र)
 (सेवाओं के लिए लागू)

दिनोंका

सेवा में,

यह साख्यक्र (अग्रणी) और विदेशी आधिकारिक सहयोग निधि के बीच हुए अहं करार-

संभवक का नाम तया पता— सं.----- दिनोंका— के अनुसरण में जारी किया गया है।

प्रिय महोश्य,

हम प्रापको मूल्यित करते हैं कि हमारे नाम पर पूर्ण उत्तिवित भूत्य के लिए हिताधिकारी के ड्राफ्ट एट राइट द्वारा उपलब्ध रकम जिसकी कुल धनराशि— (—) वेन से अधिक नहीं है, के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साख्यपत्र सं.----- खोल दिया है।

इसमें इसके साथ संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (परियोजना के संबंध में डेका सं.-----) से संबंधित दस्तावेज होने चाहिए। लेन देन के लिए ड्राफ्ट से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर अपरिवर्तनीय क्रेडिट सं.----- के अंतर्गत छोट लिखा हीना चाहिए।

यह क्रेडिट हस्तांतरणीय नहीं है।

हम एतदारा बताते हैं कि इस क्रेडिट के अंतर्गत दस्तकी शर्तों का अनुसालन करके भुगताने ये सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आवेदितों को दस्तावेजों की सुपुद्दी पर विविध स्तीकार किए जायेंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारसूचक उल्लेख के किया जाए, यह क्रेडिट "यूनिकार्म फस्टम एण्ड प्रैक्टिस फार डाकुमेंट्री ऑफिट (1974 रिवीजन) इस्टलोनस बैंकर आफकामस बोर्ड म. 290" के अनुसार है।

लेन देन करने वाले बैंक को विवेष अनुबेद :-

- (1) इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (अग्रणी और इसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किये गये निष्पादन के भूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात इस क्रेडिट के अंतर्गत भुगतान इसमें लंबाग शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किये जाने चाहिए। प्रारम्भिक भुगतानों के गामने में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बजाए हिताधिकारी का विवरण अपेक्षित है।
- (2) ऊपर उल्लिखित अहं समझौते के अनुसार जारी किए गए बचतबदला पत्र के उपर्युक्त के अनुसार विवेषी आधिकारिक सहयोग निधि से अपने भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम सेन-देन करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार ड्राफ्टों की राशि परेक्षित करने वयन देते हैं।
- (3) उपर्युक्त मद 1 में यां उत्तिवित दस्तावेजों को एक प्रति और ड्राफ्ट उत्तकी प्राप्ति के तुरन्त बाय ही हमें दें जायेंगे।
- (4) इस साख्यक्र के अंतर्गत बैंक के सभी अचें आवातकों/संभरकों के बाते से देव हैं।

प्रबद्धीय
आधिकारिक बैंक

द्वारा—
(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साख्यपत्र सं.----- का एक अधिक्षम अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि— येन जो कुल संविदा मूल्य का— प्रतिशत है।

प्रतिशत दस्तावेज़ :

प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख :

हिताधिकारी का विवरण

2. भुगतान प्रगति :

सम्पूर्ण योग : धनराशि ----- येन जो कुल संविदा मूल्य का— प्रतिशत है जिसका भुगतान निम्न प्रकार से किया जाना है :-
देय धनराशि

पहली किस्त, येन—

दूसरी किस्त येन—

अपेक्षित दस्तावेज़ : (अग्रणी प्रथम उत्तके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र संलग्न है।

MINISTRY OF COMMERCE
(IMPORT TRADE CONTROL)

PUBLIC NOTICE NO. 90-ITC(PN) |88-91

New Delhi, the 27th December, 1988

Sub : Licensing Conditions for import of equipment| services under OECF Loan for implementation of the Anpara 'B' Thermal Power Station Construction Project (2x500 MW) of the Uttar Pradesh State Electricity Board (UPSEB).

File No. IPC|23(47)|88-91.—The terms and conditions governing import of equipment|services under OECF Loan for implementation of the Anpara 'B' Thermal Power Station Construction Project (2x500 MW) of the Uttar Pradesh State Electricity Board (UPSEB), as given in Appendix to the Public Notice are notified for information.

Sd/-

K. V. IRNIRAYA,
Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX TO THE MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 90-ITC(PN) | 88-91 dated 27-12-1988.

LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF IMPORT OF GOODS AND SERVICES UNDER THE OECF LOAN FOR IMPLEMENTATION OF THE ANPARA 'B' THERMAL POWER STATION CONSTRUCTION PROJECT (2x500 MW) OF THE UTTAR PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD (UPSEB), EXTENDED BY THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND (OECF) OF JAPAN.

Section I-General Conditions

I (i) The Govt. of Japan have agreed to extend a multiyear OECF loan of Yen 100 Billion for implementation of the Anpara 'B' Thermal Power Station Construction Project (2x500 MW) of the U. P. S. E. B. on a turn-key contract basis. So far two loan agreements have been signed with the OECF for a total loan amount of Yen 38.395 Billion (OECF Loan No. ID-P. 20 for Yen 24.1 Billion signed on 26-12-1984 and No. ID-P. 45 for Yen 14.295 Billion signed on 10-2-1988). The Loan agreements for the balance amount will be signed in the next 2-3 years depending upon the annual OECF loan requirements for the project.

The OECF loan for financing the import requirements of the project is untied in favour of developing countries including India and Japan. Accordingly the goods and services to be procured under this loan can be procured from Japan and all countries (including India) enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the loan.

I (ii) Import Licence (s) under this loan can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD|CG

Committee. The value of import licence (s) issued under this loan arrangements should not exceed Yen 110.0 Billion (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the Exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the importer licence (s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN) | 74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence (s) at the exchange rate specified on the import licence (s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit". The first and second suffix to the licence code will be "SJC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to UPSEB, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (iii) Import licence (s) under this loan can be issued only on CIF basis.

I (iv) Depending on the convenience of UPSEB| importer more than one import licence may be issued under this loan, but the total value must not exceed Yen 110.0 billion (CIF) as specified at (i) above.

I (v) The extension of the validity of the import licence may on application be granted for a further period of 12 months. Requests for further extension| issue of a fresh import licence, if any, may be referred to Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (vi) Imports to be financed under the are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I (vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian Rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I (viii) Firm order must be placed on FOB|C&F basis on the overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian Licence on the supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import

licence. If firm orders as explained in para I (viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the Licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorities dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I (x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i. e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

..... Months after the receipt of Letter of Credit but to be completed latest by the end of

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-1991.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II (i) The FOB/C&F value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II (ii) The procurement of all goods and services except consulting services to be financed under the OECF loan for Anpara 'B' Thermal Power Project shall be made in accordance with the Guidelines for procurement under the OECF Loan.

(a) The U. P. S. E. B. shall procure goods and services to be financed out of the proceeds of the loan through Formal Open International Tendering with prequalification and on turnkey contract basis.

(b) The U. P. S. E. B. shall obtain the prior approval of the Fund if it wishes to adopt procurement procedures other than Formal Open International Tendering, submitting to the Fund an application for Approval of Procurement Method(s) signed by a duly authorised person.

(c) Before advertisement and/or notification of prequalification, the U. P. S. E. B. shall submit to the Fund for its approval the prequalification documents. When the prequalified firms have been selected, the U. P. S. E. B. shall submit to the Fund for its approval the list of those firms and report on the selection process giving the reasons for the selection made, attaching all relevant documents.

(d) Prior to inviting bids for procurement of goods and services, the UPSEB shall submit to the Fund for its approval all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract, specifications and drawings and all other documents related to the bidding.

(e) Prior to issuing a notice of award to the successful bidder, the U. P. S. E. B. shall submit to the Fund for its approval the analysis of bids and the proposal for award of the contract.

(f) The documents stated above will be submitted by the U. P. S. E. B. to the Department of Economic Affairs, in duplicate, for obtaining approval of OECF.

(g) The bidding documents shall state which are the eligible source countries.

II (iii) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF loan (Project Aid) the details of which are given in Section V below.

II (iv) Eligibility of supplier

The suppliers shall be nationals of the eligible source countries, or juridical persons incorporated and registered in eligible source countries, and which have its appropriate facilities for producing or providing the goods or services in the eligible source countries, and actually conduct its business there.

II (v) Permissible imports from non-eligible source countries

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than fifty per cent (50%) of the price per unit of such products in accordance with the following formulae :

$$\frac{\text{IMPORTED CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price (Ex-factory price in case of Indian Suppliers)}} \times 100$$

II (vii) Declaration in Contract

The following declaration as to the eligibility of the goods and supplier, signed and dated by the supplier, shall be added to each contract.

"I the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in _____ (name of eligible source country).

I the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than fifty percent (50%) in accordance with the following formula :

IMPORTED CIF Price + Import Duty
Supplier's FOB Price (Ex-factory price in $\times 100$
case of Indian Suppliers)

"I, the undersigned, hereby certify that _____ (Name of company) has been incorporated and registered in _____ (name of eligible source country), and is controlled by nationals of _____ (Name of eligible source countries concerned)."

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts.

III (i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

- (a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) concerning the OECF loan (Project Aid) for Anpara 'B' Thermal Power Project of U. P. S. E. B. and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.
- (b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the OECF loan agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).
- (c) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India or the one hand and the OECF on the other.
- (d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II (vii) above.
- (e) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo, informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India atleast six weeks in advance of the shipping required so that

suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian Importers require it this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV-Contract Approval by OECF

IV (i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both UPSEB and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV (ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV (iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval. A copy each of the contract will also be simultaneously sent to the Embassy of India, Tokyo and the CAA&A.

Section V-Payment to the overseas suppliers-Letter of Credit Procedure.

V (i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs the UPSEB and the CAA&A will be informed of the same. Whereafter the UPSEB should approach the Controller of Aid Accounts & Audit. (hereinafter referred to as CAA&A) Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure-II for issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-III addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure-IV (for imports) or Annexure-V (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, UPSEB, the importer's Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V (ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-IV applicable to (imports) or V (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA &A would ipso-facto apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V (iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V (iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for opening the letter of credit, for negotiations thereunder and charges if any of overseas suppliers' bankers are to be borne by the overseas supplier/importer. A letter of commitment will be issued by the OECF on receipt an amount equal to one-tenth percent (0.1%) of the contract value. This amount will be paid to itself from the loan funds by OECF.

The importer is required to deposit into the Govt. of India account the rupee equivalent of this letter of commitment charges on receipt of intimation of the payment from OECF or from the controller of Aid Accounts, Ministry of Finance. Interest from the date of payment to OECF to the date of rupee deposit (both dates inclusive) at prevailing rates will also have to be paid by the importer.

A similar charge of 0.1% is payable by the importer under the reimbursement procedure also. Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the period counting from the date of payment of the cost of imports by them to the overseas suppliers to the date of reimbursement by the OECF, shall be settled by the concerned importers bank of India by remittance to the Bank of India Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

V (v) Reimbursement Procedure

Procedure for disbursement of the proceeds of the loan for the purchase of goods and services from Indian Suppliers shall be in accordance with REIMBURSEMENT PROCEDURE of the loan agreement.

Sectoon VI—Employment of Consultants :

Consultants shall be employed in accordance with "Guidelines for the Employment of Consultants by OECF Borrowers" attached to the Loan agreement.

(i) The consulting firms shall satisfy all of the following conditions :

- (a) A majority of the subscribed shares shall be paid held by nationals of the Eligible source Countries ;
- (b) A majority of the full-time directors shall be nationals of the Eligible Source Countries ;
- (c) Such firms shall be incorporated and registered in the Eligible Source Countries.

(ii) The prior approval of OECF is required to be obtained for the following :—

- (i) Terms of Reference.

(ii) Short List of Consultants.

(iii) Letter of Invitation.

(iv) Evaluation Report including Summary Evaluation Sheet.

(iii) The following declaration as to the eligibility of the Consultant, signed and dated by the Consultant, shall be attached to each contract :

"I, the undersigned, hereby certify that _____ (name of firm) has been incorporated and registered in _____ (name of the Eligible Source Country concerned), and is an eligible consulting firm _____ per cent (____-%) of the subscribed shares being held by nationals of _____ (name of the Eligible Source Countries concerned) and _____ per cent (____-%) of the full time directors being nationals of _____ (name of the Eligible Source Countries concerned)"

(iv) When the contract is awarded to a Consultant of an eligible source country other than Japan, the contract price shall be stated and payable in Japanese Yen or United States Dollars. When the contract is awarded to a Japanese consultant, the contract price shall be stated and payable in Japanese Yen. The contract shall be subject to the approval of the Government of India/OECF.

(v) The documents stated above for approval of the Fund shall be submitted by the U. P. S. E. B. to the Fund through the Department of Economic Affairs indicating the following :

- (a) Percentage of the subscribed shares held by nationals of Eligible Source Countries.
- (b) Percentage of the full-time directors who are nationals of the Eligible Source Countries.

Section VII—Responsibility for rupee deposit.

VII (i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of importer as indicated in the appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or S.B.I. Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. Interest charges on the rupee-equivalents of the Yen payments calculated at the rate prevailing from time to time, the present rate being 12% per annum for the first 50 days and @ 18% per annum for the period of excess thereof, reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the overseas Supplier to the date of actual rupee deposit, have also to be deposited alongwith the principal payment, in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN) 83 dated 18-8-1983.

It should be noted that interest is chargeable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Overseas Supplier and also the day on which rupee deposit is made in Government Account vide Public Notice No. 74-ITC(PN) 74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN) 74 dated 12-10-1974 and Public Notice No. 31-ITC(PN) 83 dated 10-8-1983.

The importer should make separate arrangements to ascertain the amounts and dates of payments made to the supplier. Late or delayed receipt of shipping etc. documents by the importers Banker from Bank of India, Tokyo will not be acceptable as reason for waiver of partial or full amount of the interest due on the rupee deposits.

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notice No. 109-ITC(PN) |74 dated 3-8-1974 and 8-ITC(PN) |76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amount due are correctly deposited into Government account before the import documents are handed over to the importers. The importers should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their Bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amount due are correctly deposited into the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities without original shipping documents under exceptional circumstances. In case the importers fail to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further LAS to him may be stopped and the matter reported to the CCI&E so that no further import licence is issued to such an importer. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843-civil Deposits-Deposits for purchase etc. abroad-Purchase under credits/OECF Loan Agreements" Loans from the Government of Japan for the Anpara 'B' Thermal Power Station Construction Project.

VII (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Cone No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN) |68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN) |68 dated 24-10-68, No. 132-ITC(PN) |71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN) |74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN) |76 dated 12-10-1976.

VII (iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) while filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN) |71 dated

5-10-1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury challans :—

- Ministry of Finance letter of authority No. and date.
- Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note :—Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VII (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VIII—Miscellaneous Provisions.

VIII (i) Reports on utilisation of the import licence.

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VIII (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.

The licences should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VIII (iii) Disputes.

It should be understood that the Government of India, will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-II under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VIII (iv) Future Instructions.

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import

licence and for meeting all obligations under the OECF loan Agreement (Project Aid) with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VIII (v) Breach or violation.

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII (vi) List of Annexures :

Annexure I List of eligible source countries.

Annexure II Request for issue of Letter of Authority.

Annexure III Form of Letter of Authority.

Annexure IV Form of Letter of Credit (Applicable to imports).

Annexure V Form of Letter of Credit (Applicable to Services).

ANNEXURE I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. Development Countries and Territories.

(a1) Non-OPEC Developing Countries.

I. AFRICA, North of Sahara

Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara

Angola
Benin
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of
Dahomey
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando P.O.

Mozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helens and dep (2)
Sao Tome and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro, Afars and Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zambia

III. AMERICA, North end Cont.

Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands Antilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tobago

III. AMERICA, North & Central

West Indies (Br.) n.i.c.

(a) Associated States (1)

(2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Cunha, Inaccessible, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St.

1. Main Islands Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Christopher), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

(b) Dependencies (2)	Thailand Timore Viet-Nam, Rep. of Viet-Nam, Dem. Rep.
IV. AMERICA, South	VIII. OCEANIA
Argentina	Cook Islands
Bolivia	Fiji
Brazil	Gibert & Elice Is.
Chile	French Polynesia (5)
Colombia	Nauru
Falkland Islands	New Calendonia
French Guiana	New Hebrides (Br. and Fr.)
Guyana	Niue
Paraguay	Pacific Islands (US) (6)
Peru	Papua New Guinea
Surinam	Solomon Islands (Br.)
Uruguay	Tonga
V. ASIA, Middle East	Wallis and Futuna
Haharain	Western Samoa
Israel	IX. EUROPE
Jordan	Cyprus
Lebanon	Gibralter
Oman	Greece
Syrian Arab Republic	Malta
United Arab Emirates (3)	Spain
Yemen Arab Republic	Turkey
Yemen, People's D. R. (4)	Yugoslavia
VI. ASIA, South	5. Comprising the Society Islands (including Tahiti) The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.
Afghanistan	6. Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam.)
Bangladesh	(a2) Member of Association Countries of OPEC
Bhutan	Algeria
Burma	Bolivia
India M	Libyan Arab Republic
Maldivis	Gabon
Nepal	Nigeria
Pakistan	Ecuador
Sri Lanka	Venezuela
VII. ASIA, Far East	Iran
Brunei	Iraq
Hong Kong	Kuwait
Khmer Republic	Qatar
Korea, Republic of	Saudi Arabia
Laos	Abu Dhabi
Macao	Indonesia.
Malaysia	
Phillippines	
Singapore	
Taiwan	
2. Main Islands : Montserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.	
3. Ajman, Dubai, Fugairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.	
4. Including Aden and various sultante and emirates.	

ANNEXURE II

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

No. Date :

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
 Ministry of Finance,
 Department of Economic Affairs,
 UCO Bank Building, 1st Floor,
 Parliament Street,
 New Delhi-110 001.

Sub : Import of _____ from _____ under the Yen Credit No. ID-P-_____(Project Aid for 198 -8).

Sir,

In connection with the import _____ from _____ under the above mentioned Yen Credit No. ID-P-_____(Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the _____ (name of the Bank) which should be the same as given in (P) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

- (a) Name and Address of the Indian importer
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.—
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.
- (g) Gross FOB/C&F value (In Yen) of contract (in Yen).
- (h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.
- (i) Net FOB/C&F value (in Yen) for which the Letter of Authority is required.
- (j) Number and date of the contract with overseas suppliers.
- (k) Name and address of the Overseas Supplier.
- (l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (m) Expected date of completion of deliveries.
- (n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted).
- (p) Name and address of the importer's bank in India.
- (q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the OECF.
- (r) Whether the banking charges payable to Bank of India, Tokyo for operation and maintenance of Letter of Credit are to be borne by the Importers/or Supplier.
- (s) Undertaking by the importer :—

"We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc. of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government. The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the goods (material imported). In case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers are approved by us and the Payments made to the suppliers".

ANNEXURE III

(Letter of Authority Form)

No.F.

Government of India

Ministry of Finance

Department of Economic Affairs

New Delhi, the

To

The Bank of India,
 Tokyo Branch,
 Tokyo (Japan)

Subject : Import under Yen Credit (Project Aid) Loan Agreement No. ID-P-----Issue of Letter of Authority
 for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-80—entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen----- favouring M/s.-----as per attached details.

2. A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank, to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

3. Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

4. On making payment to the foreign supplier you should send to----- (Name and address of the importers' Bankers) the original shipping documents (negotiable) as well as additional complete set of the documents and a copy of the debit advice for the payments made to the supplier including the down payment if any.

5. Interest charges payable to you, for the time lag between the date of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement to you by the OECF, shall be settled by you with the concerned Importers bank in India through normal banking channels without affecting the Government of India's account. The other banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the Overseas Supplier/Importer and may, therefore, be recovered from the Supplier/Importer directly. No reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

6. As and when payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

7. This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

8. This Letter of Authority will remain valid up to-----

9. Please quote the number given at the top of this letter of instructions in all correspondence relating to the contract and also in the advice showing payment.

Yours faithfully,

(Accounts Officer)

Copy forwarded to :—

1. Importers——— with reference to their letter No.————— dated—————.

They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and Port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign nationals, the deposits should be made as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposit promptly and correctly may entail action as mentioned in the Licensing Conditions.

2. (i) Importers' Banker. This has reference to import licence No.————— date————— This letter of authorisation issued under the relevant licensing conditions governing the imports under Yen cr. dit. The licensing conditions and connected Public Notice/order etc. may be referred to and appropriate action taken concerning the import/foreign payments.

2. (ii) They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-76 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @12% per annum for the first thirty days and @18% per annum for period in excess thereof reckoned for the period between the date of payment to supplier/date of reimbursements to Bank of India and the date on which the rupee equivalents are deposited in the Government Account is also required to be deposited into the Government of India Account in terms of Public Notice No. 31-ITC(PN)/83 dated 10-8-1983. The interest is payable for both the days i.e. the day on which it is made to the Overseas Suppliers and also the date on which rupee deposits are made into Government Account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the challan or the SBI, Tis Hazari, Delhi. In this connection, their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of account to be credited is "K-Deposits & Advances-843-Civil Deposit-Deposit for purchases etc. abroad under Purchases under Credit/Loan Agreements"—Loans from the Government of Japan————— billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P————— for 198 -8

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

Interest charges payable to the Bank of India, Tokyo for the time lag between the date of payment to the supplier and the date of its reimbursement to the Bank of India, Tokyo by the OECF shall be settled directly by you with the Bank of India, Tokyo through normal banking channels without affecting the Government of India's account.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Gode Building, 4-1, Otemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100 Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

ANNEXURE IV
Form OECF-LC I

**Irrevocable Letter of Credit
 (Applicable for goods)**

Date:

This letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. _____ Date _____ between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

To _____

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. _____ in your favour for int of _____ for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y _____ (Say yen) available by your drafts at sight for full value drawn on us, to be accompanied by the following documents:

Signed commercial invoice in full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight and Notify" other documents evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No. _____ if any) from to _____ partial shipments and permitted. Transhipment is permitted. Bills of lading must be dated not later than _____ Drafts must be presented for negotiation not later than _____

All Drafts and documents under this credit must be marked

"Drawn under _____ dated _____ (if any) _____
 irrevocable credit No.
 and Import Reference No.(s) _____

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentations and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank:

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.

2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to _____

3. All banking charges under this credit are for the account of importer/supplier.

Yours faithfully,

.....
 (a commercial bank)

By: _____
 (Authorized signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No. _____.

I. Initial Payment

Amount: Y _____

being _____ % of the total contract price.

Required documents:

Latest presentation date:

II. Intermediate Payment (if any)

Amount: Y _____

being _____ % of the total contract price.

Required documents:

Latest presentation date:

III. Payment against shipping documents

Amount : Y _____

being _____ % of the total contract price.

Note : This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE V

Form OECF-LC II

**Irrevocable Letter of Credit
(Application for Services)**

Date:

This letter of credit has been issued pursuant to
Loan Agreement No. _____
Dated _____
between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

To _____

(Name and address of the Supplier)

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. _____ in your account for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y. _____ (Say Yen). Available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, being (Contract No. _____ with regard to _____ Project).

must be presented for negotiation not later than

Drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No. _____". Credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly presented and delivery of documents to the drawee.

Otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special instructions to the negotiating bank:

1. After receipt of the original statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments the beneficiary's Statement is required instead of the above mentioned Statement of Performance.
2. After obtaining the reimbursement for our payment from the OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.
3. A copy of the documents as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.
4. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By: _____
(Authorized Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No. _____

I. Initial Payment

Amount: Y_____

being _____ % of the total contract price

Required documents: beneficiary's Statement

Latest presentation date:

II. Progress Payment:

Aggregate amount: Y_____

being _____ % of the total contract price to be paid as follows:

1st Instalment:

Y_____

2nd Instalment

Y_____

.....

Required document: A copy of state of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a
of which is attached hereto.